तीन मिनट में 100 फीसदी सब्सक्राइब हुआ पतंजलि का 250 करोड़ का डिबेंचर

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

कोरोनावायरस और लॉकडाउन के चलते मंदी की आशंकाओं के बीच भारतीय निवेशकों ने गुरुवार को 250 करोड़ रुपए मूल्य का एक डिबेंचर महज तीन मिनट में 100 फीसदी सब्सक्राइब कर डाला। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद का यह नॉन कंवर्टिबल डिबेंचर खुलते ही पूरा सब्सक्राइब हो गया।

पतंजलि आयुर्वेद की ओर से जारी वक्तव्य के मुताबिक, वह इस पैसे का इस्तेमाल अपनी पूंजीगत जरूरतें पूरी करने और सप्लाई चेन मजबूत बनाने में करेगी। कंपनी ने निवेशकों का रिस्पॉन्स ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह कंपनी पर लोगों का भरोसा दिखाता है। पतंजलि के इस डिबेंचर पर कूपन दर (ब्याज दर) 10.10 फीसदी रखी गई है। इसकी मैच्योरिटी अवधि तीन साल की है और यह 28 मई 2023 को मैच्योर होगा। डबल ए रेटिंग वाले ये डिबेंचर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होंगे।

एविएशन इंडस्ट्री तभी उबर सकती है जब कोरोना महामारी के बाद स्थिति सामान्य हो और एयरलाइंस सर्विस पूरी क्षमता से चलेः लोहानी

धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया | नई दिल्ली

भास्कर इंटरव्यू एअर इंडिया के दो बार चेयरमैन रहे अश्विनी लोहानी से एविएशन सेक्टर के रिवाइवल पर विशेष बातचीत

कोरोनावायरस महामारी के कारण हुए देश व्यापी लॉकडाउन के बाद धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियां खोलने के क्रम में भारत सरकार ने फ्लाइट्स को उड़ान की अनुमति दे दी है। ऐसे में वर्तमान में अलग-अलग राज्यों ने इसको लेकर अलग-अलग प्रतिक्रिया दी और इसके नियम बनाए हैं। मिडिल सीट खाली रखी जाए या नहीं इस पर भी खासी बहस छिड़ी हुई है। पहले से ही वित्तीय दबाव में चल रहीं विमानन कंपनियां कैसे इसे चालू रख सकती हैं, भविष्य में एविएशन सेक्टर की क्या स्थिति बनेगी जैसी बातों पर इस क्षेत्र के विशेषज्ञ और एअर इंडिया के दो बार चेयरमैन रहे अश्विनी लोहानी ने दैनिक भास्कर से विशेष बात की। चर्चा के प्रमुख अंशः

▪ कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन से इंडस्ट्री को किस तरह की परेशानी का समाना करना पड़ रहा है?

कोरोना महामारी के कारण एविएशन इंडस्ट्री में ठहराव आ गया है। एयरलाइन ऐसा बिजनेस है जब यह सामान्य दिनों में भी चल रहा था तब भी वित्तीय रूप से परेशानी में ही था। अभी जबकि प्लेन जमीन पर ही हैं, ऐसे में यह कंपनियों के लिए वित्तीय आपदा जैसा है क्योंकि एयरलाइंस के खर्चे जैसे मजदूरी, मैंटेनेंस और अन्य स्थाई खर्च लगातार वहन करने पड़ रहे हैं जबकि रेवेन्यू शून्य है।

▪ इंडस्ट्री किन उपायों से उबर सकती है?

सरकार कोई वित्तीय पैकेज दे भी देती है तो भी कंपनियों का काम अधिक दिन तक नहीं चल सकता। एविएशन इंडस्ट्री तभी उबर सकती है जब कोरोना का असर खत्म हो और एयरलाइन्स सर्विस पूरी क्षमता से चलने लगें। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है।

▪ हवाई यात्राएं कब से सामान्य हो सकती हैं?

मुझे लगता है कि फ्लाइट्स की स्थिति तभी सामान्य हो सकती है जबकि यह महामारी खत्म हो जाए।

▪ यात्रियों की दृष्टि से किस-किस प्रकार की सावधानियां एयरलाइंस को बरतनी चाहिए?

एयरलाइंस को फेस मास्क और सैनेटाइजर यात्रियों को मुहैया कराना चाहिए। यात्रियों को बोर्डिंग के समय और टर्मिनल में भी फिजिकल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स खत्म करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और सैनेटाइजेशन हरसंभव स्थान पर किया जाना चाहिए।

▪ महामारी के बीच विमान में मिडिल सीट को खाली छोड़ने पर काफी चर्चा हो रही है, आप क्या सोचते हैं?

मिडिल सीट को अगर एयर लाइन्स खाली भी छोड़ती हैं तो भी सोशल डिस्टेंसिंग के छह फीट की दूरी के नियम का पालन तो फिर भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि सीट तो 17 इंच की ही है। आवश्यक है कि यात्रियों को मास्क, ग्लव्स और उनका प्रॉपर सैनेटाइजेशन किया जाए। स्टाफ भी सख्ती से नियमों का पालन करे।

▪ एयर लाइन कंपनियों ने बड़ी संख्या में प्लेन का ऑर्डर दिया था? क्या वे इनकी डिलीवरी में लेने में सक्षम होंगी?

एयर ट्रेवल में बड़ी संख्या में गिरावट निकट भविष्य में देखने को मिलेगी, इसलिए मुझे लगता है कि देश में मौजूद करीब 650 विमानों के द्वारा उड़ान भर पाना संभव नहीं है। इस प्रकार के मुद्दे पर एयरलाइंस कंपनियों और एयरक्राफ्ट निर्माता या लीज पर विमान देने वाली कंपनियों में अवश्य बात करने की आवश्यकता है।

▪ विमानों के तय समय पर न मिलने से क्या नए रूट्स पर कंपनियां यात्रा शुरू कर पाएंगी?

जैसा कि मैंने पहले ही कहा सभी करीब 650 विमानों की उड़ानें एक साथ शुरू नहीं हो पाएंगी। ऐसे में अगर किसी नए रूट की जरूरत दिखाई देती है तो उस पर आसानी से उड़ानें शुरू की जा सकती हैं क्योंकि मौजूदा रूट्स पर लोड घट गया है।

▪ क्या छोटे शहरों के रूट्स पर हवाई यात्राएं करा पाना कंपनियों के लिए संभव होगा?

जब तक महामारी पर नियंत्रण नहीं पा लिया जाता मुझे नहीं लगता है कि एयरलाइन कंपनियां नए रूट या छोटे शहरों की कनेक्टिविटी की ओर ध्यान दे पाएंगी।

▪ एयर इंडिया का विनिवेश क्या तय समय में हो पाएगा?

एयर इंडिया के विनिवेश के सभी कारण अभी भी बने हुए हैं। अब इस प्रक्रिया के लिए कोई बोली लगाने आगे आता है या नहीं वह नीलामी प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान यह कर पाना खासा चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

बिजनेस ब्रीफ

सरकारी बैंकों में 1.5 लाख करोड़ रु. डालने की जरूरत, एनपीए दोगुना होगा

नई दिल्ली| कोरोना के प्रकोप के बीच सरकारी बैंकों का एनपीए बढ़कर दो गुना हो जाने का अंदेशा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में सरकारी बैंकों में 1.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डालने की जरूरत पड़ सकती है। घटनाक्रम से जुड़े बैंकिंग सूत्रों ने यह जानकारी है। शुरुआत में बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। लेकिन इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। देशव्यापी लॉकडाउन कारोबारी गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इससे लोन डिफॉल्ट के मामले बढ़ने का अंदेशा है।

मई में निर्यात की गिरावट दस फीसदी तक रह सकती है सीमितः गोयल

नई दिल्ली| वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने देश के निर्यात मई में अप्रैल से बेहतर होने की उम्मीद जताई। अप्रैल में निर्यात 60.28% गिर गया था जो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। जून में स्थिति कुछ ठीक हो सकती है और गिरावट 10% सीमित रह सकती है। भारतीय उद्योग परिसंघ के निर्यात सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का विविधीकरण और नए बाजार की खोज जैसे प्रमुख लक्ष्यों के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है।

मारुति ने एचडीएफसी के साथ किया समझौता, कार लोन में होगी आसानी

नई दिल्ली | मारुति सुजुकी इंडिया ने गुरुवार को कहा कि उसने नई कार खरीदने वालों के लिए आसान शर्तों पर कर्ज के लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इस योजना में फ्लेक्सिबल मासिक किस्त (ईएमआई) का विकल्प शामिल है। इसके तहत ग्राहक हर साल तीन महीने कम ईएमआई का लाभ उठा सकते हैं। ग्राहकों के हाथ में आने तक गाड़ी की कुल कीमत का 100 प्रतिशत तक कर्ज ले सकते हैं। पहले छह महीने कर्ज की किस्त प्रति लाख, प्रति माह 899 रुपए से शुरू हो रही है।

शेयर बाजार

आयशर मोटर्स के शेयर एनएसई में 7.34% उछलकर बंद हुए

मुंबई | आयशर मोटर्स के शेयर एनएसई में गुरुवार को 7.34% बढ़त के साथ 16,065 रुपए पर बंद हुए। एलएंडटी के शेयर में 5.78% की तेजी रही। कंपनी के शेयर 900 रुपए पर बंद हुए।

टॉप-5 गेनर्स एनएसई 50

शेयर	बंद भाव	बदलाव	
जी एंटरटेनमेंट	180.20	15.75	9.58%
आयशर मोटर्स	16,065.00	1,098.05	7.34%
एलएंडटी	900.00	49.15	5.78%
हीरो मोटोकॉर्प	2,288.30	112.65	5.18%
एचडीएफसी बैंक	947.50	43.85	4.85%

टॉप-5 लूजर्स एनएसई 50

शेयर	बंद भाव	बदलाव	
विप्रो	199.40	1.85	0.92%
आईटीसी	191.00	1.15	0.60%
सिप्ला	629.75	3.30	0.52%
एसबीआई	157.90	0.70	0.44%
जेएसडब्ल्यू स्टील	184.00	0.80	0.43%

शेयर बाजार • विदेशी निवेशकों ने की मेटल, ऑटो, और प्राइवेट बैंकों के शेयरों मे बिकवाली

एफआईआई की होल्डिंग मार्च तिमाही में पांच साल के निचले स्तर पर पहुंची

मार्च में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से 1,18,203 करोड़ रुपए निकाले

भास्कर न्यूज | मुंबई/नई दिल्ली

इस साल जनवरी से मार्च की तिमाही में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में जमकर बिकवाली की है। एनएसडीएल के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने भारतीय बाजार में जनवरी में 957 करोड़ रुपए और और फरवरी में 8,970 करोड़ करोड़ रुपए निवेश किए थे। लेकिन मार्च में उन्होंने 1,18,203 करोड़ रुपए निकाले हैं। मेटल, ऑटो और प्राइवेट बैंकों के शेयरों में एफएफआई की बिकवाली देखने को मिली। इसका नतीजा यह रहा कि निफ्टी 500 की कंपनियों में मार्च तिमाही के दौरान एफआईआई की होल्डिंग घटकर पांच साल के निचले स्तर 21% पर आ गई। इसमें तिमाही आधार पर 1.40% और सालाना आधार पर 0.80% की कमी आई है।

यह जानकारी ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट से सामने आई है। इसके मुताबिक एफआईआई ने तिमाही आधार पर निफ्टी 500 की 67% कंपनियों में निफ्टी 50 की 90% कंपनियों में अपनी ऑनरशिप कम की है।

एफआईआई ने निफ्टी 500 की 67% कंपनियों में ऑनरशिप कम की

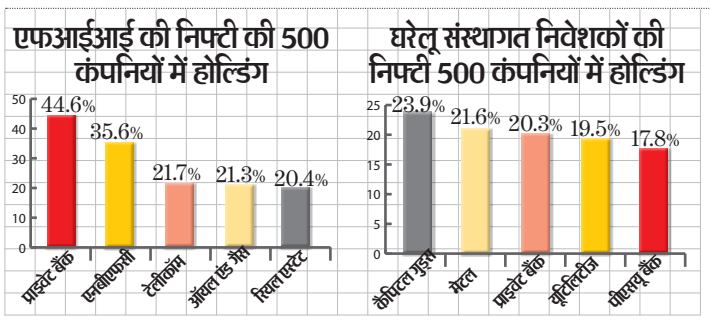

एफआईआई-डीआईआई ऑनरशिप रेशियो सबसे कम

पिछले पांच साल में घरेलू पूंजी बचत का प्रभाव लगातार बढ़ा है। एसआईपी के जरिए होने वाला निवेश भी बढ़ा है। इससे निफ्टी 500 की कंपनियों में एफआईआई-डीआईआई ऑनरशिप रेशियो सबसे निचले स्तर पर आ गया है। पिछले पांच साल में यह 2.2 गुना से घटकर 1.4 गुना पर आ गया है। बीते एक साल में एफआईआई-डीआईआई रेशियो इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ा है। जबकि टेलीकॉम, रियल एस्टेट आदि में कम हुआ।

प्रमोटरों ने होल्डिंग सालाना आधार पर 50.5% तक बढ़ाई

तेज गिरावट के बीच प्रमोटरों ने कम कीमत में शेयर खरीदकर निफ्टी 500 की कंपनियों में होल्डिंग बढ़ाई है। इसमें तिमाही आधार पर 1.30% और सालाना आधार पर 50.5% की बढ़त देखने को मिली है। फ्री-फ्लोट के अनुपात में एफआईआई की ऑनरशिप 1.80% घटकर 42.3% रही। जबकि डीआईआई की ऑनरशिप फ्री-फ्लोट के अनुपात में तिमाही आधार पर 0.90% बढ़ गई है।

चार हफ्तों की ऊंचाई पर सेंसेक्स, दो दिन में 1,591 अंक मजबूत

मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच मासिक वायदा सौदों के अंतिम दिन गुरुवार को देश के शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 595.37 अंक (1.88%) मजबूत होकर 32,200.59 पर बंद हुआ। निफ्टी में 175.15 अंक (1.88%) की तेजी रही। यह 9,490.10 पर बंद हुआ। यह इनका चार हफ्तों का उच्चतम स्तर है। बीते दो दिन में सेंसेक्स 1,591 अंक और निफ्टी 461 अंक मजबूत हो चुका है। 29 अप्रैल को सेंसेक्स 32,720 के स्तर और निफ्टी 30 अप्रैल को 9,860 के स्तर पर था।

भास्कर गाइड

टीडीएस में कमी का किसे होगा फायदा, क्या अड़चनें, कैसे लें लाभ? यहां जानें

टीडीएस में 25% कमी का फायदा 14 मई से

कोरोना संकट की वजह से केंद्र सरकार ने आयकर के नियमों में संशोधन किया है। आय के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को लेकर सरकार ने 25 प्रतिशत की बड़ी छूट का ऐलान किया था। हालांकि ये छूट नौकरी पेशा लोगों को नहीं मिलेगी। ऐसे में इस छूट का लाभ किसको मिलेगा? इसमें कौन-सी बातों का विशेष ध्यान रखना है? ऐसे सभी सवालों के जवाब भास्कर आपके लिए लाया है..

कब से लागू होगा फैसला

चिर अमृत लीगल एलएलपी के एसोसिएट पार्टनर मुकेश सोनी के मुताबिक, सरकार ने 31 मार्च को अध्यादेश जारी कर आयकर से संबंधित जरूरी अनुपालन, नोटिस और आदेशों के लिए निर्धारित अवधि 31 मार्च को बढ़ाकर 30 जून की थी। लेकिन टीडीएस व टीसीएस की दरों में 25 प्रतिशत की कमी का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 मई को किया था। यानी टीडीएस की दरें 14 मई से कम होना माना जाएगा।

फिर 13 मई से पहले क्या

13 मई से पहले की अवधि के लिए पूर्व की भांति टीडीएस कटौती होगी। यानी 13 मई या उससे पहले की गई स्रोत पर कर कटौती को पहले की दरों के अनुसार ही तय समय में जमा कराना होगा। जबकि 14 मई के बाद स्रोत पर की गई टैक्स कटौती को कम की गई दरों के हिसाब से सरकार के पास जमा करना होगा।

वेतनभोगी तबका कैसे ले सकता है इसका लाभ

वेतनभोगी तबके को टीडीएस में कटौती के लाभ से बाहर रखा गया है। हालांकि वेतनभोगी को दूसरे स्रोतों से हुई आमदनी जैसे कि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज, मकान किराया आदि पर वेतनभोगी भी स्रोत पर कर कटौती की दरों में कमी का फायदा उठा सकते हैं। गैर वेतन भोगियों जैसे कि डॉक्टर्स, कान्ट्रेक्टर्स, वकील, सीए आदि को ही टीडीएस में छूट का सीधा फायदा मिल सकता है।

नौकरी पेशा वालों को इसका लाभ नहीं

अधिनियम में अभी जरूरी बदलाव नहीं हुए हैं

सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए आयकर में संशोधन

के उचित कदम उठाए हैं। यह भी संभावना है कि 30 जून की डेडलाइन को और आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य बात है कि स्रोत पर टैक्स् कटौती में कमी के लिए लिए उठाए गए कदमों पर अधिनियम में आवश्यक बदलाव सरकार ने अभी तक नहीं किए हैं।

मुकेश सोनी, एसोसिएट पार्टनर , चिर अमृत लीगल एलएलपी

सैलरीड क्लास को भी इसका फायदा मिले

सैलरीड पर्सन को भी टीडीएस छूट को फायदा मिले तो ज्यादा लोगों के पास अतिरिक्त पैसा बचेगा। इससे अर्थव्यवस्था में और डिमांड बढ़ सकेगी।

केंद्र सरकार को एडवांस टैक्स जमा करने की बाध्यता में भी राहत देनी चाहिए। इससे बड़े तबके को फायदा मिल सकेगा।

हरिगोपाल पाटीदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट

क्या टैक्स जमा करने की तारीख भी बढ़ गई है?

टीडीएस कटौतीकर्ता के लिए सिर्फ रिटर्न भरने की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई है। लेकिन टैक्स जमा करने की अवधि में कोई छूट नहीं मिली है। यह अब भी मई के लिए 7 जून तक ही है। हालांकि, 20 मार्च से 29 जून तक देरी से टैक्स जमा करने पर वार्षिक ब्याज दर 18 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी की दी गई है। कटौतीकर्ता के लिए 30 जून तक पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन को भी माफ करने का फैसला किया गया है।

लॉकडाउन से 1.2 करोड़ लोग भीषण गरीबी में चले जाएंगे

वर्ल्ड बैंक ने भारत पर लॉकडाउन के संभावित असर पर रिपोर्ट जारी की

एजेंसी | नई दिल्ली

वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत की 1.2 करोड़ आबादी लॉकडाउन की वजह से भीषण गरीबी में चली जाएगी। पूरी दुनिया में लगभग 5 करोड़ लोग महागरीब हो जाएंगे। देश में गरीबी खत्म करने के लिए पिछले एक दशक में जो काम हुआ है वह मात्र कुछ महीनों में धुल जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में जितने लोग कोरोनावायरस इंफेक्शन से मरेंगे, उससे ज्यादा गरीबी और भूख से मरेंगे।

यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी स्टडी के मुताबिक 10.4 करोड़ भारतीय, वर्ल्ड बैंक द्वारा लोवर मिडिल इनकम

12.2 करोड़ भारतीय अप्रैल महीने में बेरोजगार हुए

अप्रैल में 12.2 करोड़ भारतीय बेरोजगार हो गए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) ने अपनी नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित डेली वेज वर्कर और स्मॉल बिजनेस में काम करने वाले लोग हैं। हॉकर्स, रोडसाइड वेंडर्स, निर्माण सेक्टर में लगे कामगार, ऑटो और रिक्शाचालक भी इस सूची में ऊपर हैं।

कंट्री के लिए निर्धारित 3.2 डॉलर (करीब 240 रु.) प्रति दिन आय की सीमा से नीचे आ जाएंगे। इससे गरीबी में रहने वाला लोगों का अनुपात 60% (81.2 करोड़) से 68% (92 करोड़) पर पहुंच जाएगा।

पटरी पर लौट रही है फ्रांस की अर्थव्यवस्था, पेरिस में शॉपिंग सेंटर और दुकानों का खुलना शुरू हुआ

पेरिस | फ्रेंच फैशन हाउस और लग्जरी रिटेल कंपनी लुई वितां शॉप के आगे खरीदारी के लिए पहुंचे ग्राहक। फ्रांस अब कोरोनावायरस महामारी से धीरे-धीरे उबरने लगा है। राजधानी पेरिस सहित कई शहरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दुकानों का खुलना भी शुरू हो गया है। हालांकि, वहां भी अन्य देशों की तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य है। फ्रांस में कोरोनावायरस से अब तक 1.83 लाख लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 28,599 लोगों ने जान गंवाई है।

भास्कर खास • जरूरत के मुताबिक एपल के लैपटॉप और कंप्यूटर के हार्डवेयर चुन पाएंगे भारतीय यूजर

एपल अब भारतीय ग्राहकों को दे रही है कस्टम मैकबुक और मैक कंप्यूटर बनवाने का मौका, करीब एक महीने में होगी डिलीवरी

एजेंसी | नई दिल्ली

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक एपल अब भारतीय बाजार में अपनी पैठ मजबूत बनाने में जुट गई है। इसी क्रम में कंपनी ने अब भारतीय ग्राहकों को भी कस्टम मैकबुक और मैक पीसी बनवाने का मौका दे रही है। यानी अब आप अपनी मर्जी और जरूरत के मुताबिक इन लैपटॉप और डेस्कटॉप का कॉन्फिगरेशन हासिल कर पाएंगे। इसे कॉन्फिगर टू ऑर्डर (सीटीओ) या बिल्ड टू ऑर्डर (बीटीओ) कहा जाता है।

इस पेशकश के तहत ग्राहक अपने मैक प्रोडक्ट के रैम, रोम, या ग्राफिक पावर कनिफिगरेशन का चुनाव कर पाएंगे। प्रोडक्ट की कीमत कॉन्फिगरेशन के हिसाब से कम या ज्यादा होगी। पसंदीदा कॉन्फिगरेशन वाले प्रोडक्ट अधिकृति एपल डीलर से खरीदे जा सकते हैं। एपल ने अपने पूरे मैक पोर्टफोलियो मैकबुक एयर, मैक मिनी, आईमैक आदि के लिए यह पेशकश की है।

कॉन्फिगर टू ऑर्डर या बिल्ड टू ऑर्डर योजना अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों में पहले से जारी थी। एपल ने जब हाई-एंड प्रोडक्ट बनाना शुरू किया तब इसकी जरूरत पड़ी, ताकि यूजर अपनी पंसद के हिसाब से हार्डवेयर चुन सके। उन बाजारों में एपल अपनी इस पेशकश को बढ़-चढ़कर प्रचारित भी करती थी। भारत में यह योजना नहीं थी लिहाजा यहां के यूजर को वही प्रोडक्ट लेने होते थे जो कंपनी मुहैया कराती थी। इनमें ज्यादातर बेसिक मॉडल होते थे।

2021 में भारत में खुलेगा एपल का पहला रिटेल स्टोर

एपल इस साल भारत में अपना पहला ऑनलाइन रिटेल स्टोर खोलने जा रही है। इसके अलावा कंपनी अगले साल देश में पहला फिजिकल रिटेल स्टोर भी खोलेगी। इससे एपल केयर की सर्विस भी भारतीय ग्राहकों को भारत में ही मिल सकेगी।

उदाहरण के तौर पर 13 इंच के मैकबुक प्रो भारत में दो वर्जन में लॉन्च किया गया था। इसमें अधिकतम रैम 16जीबी तक था। लेकिन, अब भारतीय यूजर इसमें 10वें जेनरेशन तक के क्वाड कोर इंटेल प्रोसेसर लगवा सकेंगे। साथ ही 32 जीबी तक रैम और 4टीटी तक एसएसडी स्टोरेज भी चुन सकेंगे। एपल ने कहा है कि वे इन कस्टम मैक लैपटॉप और कंप्यूटर की डिलीवरी करीब एक महीने में करेंगी। समयसीमा हार्डवेयर की उपलब्धता पर निर्भर हो सकती है। एपल हाल-फिलहाल भारत में ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश में है। बिक्री के इसके आंकड़े भारत में अब भी उस स्तर के नहीं है जिस स्तर के पश्चिमी देशों और चीन व जापान जैसे एशियाई बाजारों में हैं।

माइक्रोसॉफ्ट भी जियो में 15.2 हजार करोड़ निवेश कर सकती है

एजेंसी | नई दिल्ली

मुकेश अंबानी कोरोना काल का इस्तेमाल अपनी कंपनी को कर्ज मुक्त करने के लिए कर रहे हैं। पांच सप्ताह के भीतर जियो को पांच निवेशक मिले हैं। इन निवेशकों ने कंपनी में 75 हजार करोड़ रुपए के करीब निवेश किया। ताजा जानकारी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट भी जियो में 200 करोड़ डॉलर (15 हजार करोड़ रुपए) निवेश कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट जियो प्लेटफॉर्म्स में 2.5 फीसदी हिस्सेदारी खरीदना चाहती है। फरवरी में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा था कि वह रिलायंस जियो के साथ डेटा सेंटर में पार्टनरशिप करना चाहते हैं।

गूगल खरीद सकती है आइडिया में हिस्सेदारी

गूगल टेलीकॉम कंपनी में बन सकती है पांच प्रतिशत की भागीदार

एजेंसी | नई दिल्ली

पिछले एक महीने में जियो प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक सहित अन्य विदेशी निवेशकों द्वारा 78,562 करोड़ रुपए निवेश के बाद अब गूगल भी वोडाफोन आइडिया में निवेश के मौके तलाश रही है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही है। भारत के बढ़ते मोबाइल मार्केट को देखते हुए ग्लोबल प्लेयर इंडियन टेलीकॉम कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गूगल वोडाफोन आइडिया में 5 फीसदी हिस्सेदारी खरीद सकती है। वर्तमान में आदित्य बिड़ला ग्रुप की यह कंपनी वित्तीय संकटों से घिरी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अक्टूबर में एजीआर बकाए मामले में करोड़ों रुपए के जुर्माने के बाद वोडाफोन आइडिया का भविष्य अनिश्चित हो गया था। कंपनी पर 58,254 करोड़ का एजीआर बकाया निकला था। कंपनी ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट को 6,854 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया है। यह डील होने से वोडाफोन आइडिया के एक बार फिर से टेलीकॉम मार्केट की दौड़ में वापस आ जाएगी। एजीआर बकाया मामले से कंपनी को काफी नुकसान हुआ था।